



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 2006/वैशाख 11, 1928

No. 179]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 2006/VAISAKHA 11, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2006

सं. 40/2006-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 260(अ).— केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.4.1 और 4.4.2 के अनुसार जारी किए गए निशुल्क आयात प्राधिकार (जिसे इसके बाद उक्त प्राधिकार कहा गया है) के अधीन भारत में आयात की गई सामग्रियों को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, 8 और 9 के अधीन क्रमशः उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क, संरक्षण शुल्क और प्रतिपाटन शुल्क में निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट प्रदान करती है अर्थात् :-

- (i) कि आयात की गई सामग्री का वर्णन, मूल्य और मात्रा उक्त प्राधिकार के अंतर्गत आते हैं और उक्त प्राधिकार को नामे के लिए निकासी के समय सीमाशुल्क के समुचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ;

बशर्ते कि विदेशी व्यापार नीति की प्रक्रियाओं की हैण्ड बुक (भाग-I) के पैराग्राफ 4.55.3 में निर्दिष्ट परिणामी उत्पाद के संबंध में, उक्त प्राधिकार में अनुज्ञात सामग्रियों अथवा मध्यवर्ती आपूर्ति हेतु एक निशुल्क आयात प्राधिकार, जैसा भी मामला हो, उसी गुणवत्ता, तकनीकी विशेषताओं और विनिर्देशनों का होगा जो उक्त परिणामी उत्पाद में प्रयोग की गई सामग्रियों का हो ।

बशर्ते और कि उक्त परिणामी उत्पाद के संबंध में निर्यातक प्रयुक्त माल की गुणवत्ता, तकनीकी, विशेषताओं और विनिर्देशनों के संबंध में लदान बिल में एक घोषणा करेगा ;

- (ii) कि जहां निर्यात बाध्यता को पूरा करने के पश्चात् आयात होता है, वहां लदान बिल संख्या (संख्याएं) और तारीख (तारीखें) और मात्रा और परिणामी उत्पाद का पोत पर्यन्त निःशुल्क (पो.न.नि.) मूल्य उक्त प्राधिकार पर पृष्ठांकित किए जाते हैं :

बशर्ते कि जहां आयात निर्यात बाध्यता को पूरा करने से पहले किया जाते हैं, वहां निर्यात किए जाने वाले परिणामी उत्पाद की मात्रा और पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को उक्त प्राधिकार में पृष्ठांकित किया जाता है ;

- iii) आयातकर्ता, आयातित सामग्रियों की निकासी के समय ऐसे प्रतिभू या ऐसी प्रतिभूति सहित और ऐसे प्रपत्र और ऐसी राशि के लिए जो उप सीमाशुल्क आयुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा, जैसा भी मामला हो, विनिर्दिष्ट की जाए, स्वयं को आबद्ध करते हुए एक बंधपत्र निष्पादित करता है कि ऐसी छूट जिसकी बाबत इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है, यदि न दी जाए तो मांग किए जाने पर उक्त सामग्री की निकासी की तारीख से पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित उतनी रकम का संदाय करेगा, इसमें अंतर्विष्ट ऐसी आयातित सामग्री पर उद्ग्रहणीय शुल्क के बराबर हो :

बशर्ते निर्यात बाध्यता के पूर्णतः उन्मोचन के पश्चात् किए गए आयात की बाबत बंधपत्र की आवश्यकता नहीं होगी ;

- (iv) यह कि आयात और निर्यात मुम्बई, कोलकाता, कोचीन, मगदल्ला, काकीनाड़ा, कांडला, मंगलौर, मारमागोवा, चैन्नई, नावाशेवा, (रोजी जामनगर सहित) पारादीप, पीपाव, सिक्का, तूतीकोरीन, विशाखापट्टनम, दाहेज, मुद्रा, नागापट्टिनम, ओखा, बेदी, मुल्दवारका, पोर्बंदर, धरमतार और वाड़ीनार या अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, मुम्बई, कोलकाता, कोयम्बटूर, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, चैन्नई, श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम, वाराणसी, नागपुर और कोचीन, राजासांसी (अमृतसर) और लखनऊ (अमौसी) स्थित किसी विमानपत्तन द्वारा अथवा आगरा बंगलौर, कोयम्बटूर, दिल्ली, फरीदाबाद, गोहाटी, गुन्टूर, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कानपुर, लुधियाना, मुरादाबाद, नागपुर, पिम्परी (पुणे) पीतमपुर (इन्दौर), सूरत, तिरुपुर, वाराणसी, नासिक, रूद्रपुर (नैनीताल), दिघी (पुणे), बड़ोदरा, दौलताबाद (वंजारवाड़ी और मालीवाड़ा), वालुज (औरंगाबाद), अनापार्थी (आन्ध्र प्रदेश), सेलम, मालनपुर, सिंगनालुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अहमदाबाद, भिवाड़ी, मदुरई, भीलवाड़ा, पांडिचेरी, गड़ीहरसरू, भटिण्डा, दम्पर (डेरा बासी), छेहराता (अमृतसर), करूर, मिराज, रिवाड़ी, भुसावल, जमशेदपुर, सूरजपुर, दादरी, तूतीकोरीन, कुंडली, भदौही, रायपुर, मंडीदीप, दुर्गापुर और बाबरपुर अथवा स्थित किसी अन्तरदेशीय कंटेनर डिपो द्वारा या राणाघाट, सिंहबाद, रक्सौल, जोगबानी, नौतनवा (सौनोली), पैटरापोल और महादीपुर, नेपालगंज रोड दाबकी अगरतल्ला, सुतारखंडी, अमृतसर, रेल कार्गो और अट्टारी रोड अथवा विशेष आर्थिक जोन जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 76-क के तहत निर्दिष्ट हो, स्थित किसी भूमि सीमाशुल्क स्टेशन द्वारा किया जाता है ।

बशर्ते कि सीमाशुल्क आयुक्त, विशेष आदेश द्वारा या सार्वजनिक नोटिस द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसके द्वारा विहित की जाएं, किसी अन्य समुद्री पत्तन/विमानपत्तन/अंतरदेशीय कंटेनर डिपो से या किसी भू-सीमाशुल्क स्टेशन द्वारा आयात और निर्यात अनुज्ञात कर सकेगा ;

- (v) निर्यात बाध्यता, जैसा कि उक्त प्राधिकार में (मूल्य और मात्रा दोनों के अनुसार) निर्दिष्ट है, का उन्मोचन उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा भारत में विनिर्मित परिणामी उत्पादों का निर्यात करके प्रदान की जाए जो उक्त प्राधिकार में निर्दिष्ट हो और जिसके संबंध में नियम 18 के तहत में (परिणामी उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों पर प्रदत्त शुल्क रियायत) अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियम, 2002 के नियम 19 के उप-नियम 2 अथवा सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के सेनवेट क्रेडिट के तहत सुविधा उक्त प्राधिकार के प्रति आयातित/प्राप्त की गई सामग्रियों के संबंध में न ली गई हो :

बशर्ते कि कोई अग्रिम मध्यवर्ती प्राधिकार धारक नीति के पैरा 4.1.3 (ii) के अनुसार निर्यातक को परिणामी उत्पाद की आपूर्ति करके निर्यात बाध्यता का निर्वहन करेगा;

- (vi) आयातकर्ता, उप सीमाशुल्क आयुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त, जैसा भी मामला हो, के समाधानप्रद रूप में निर्यात बाध्यता उन्मोचन के साक्ष्य निर्यात बाध्यता के पूरा करने के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति से तीस दिवस की अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो उप सीमाशुल्क आयुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रस्तुत करता है ;
- (vii) कि उक्त प्राधिकार के तहत निर्यात बाध्यता का पूर्व निर्वहन करने से पूर्व छूट प्राप्त सामग्रियों का निपटान नहीं किया जाएगा अथवा इनका प्रयोग किसी भी तरीके से नहीं किया जाएगा सिवाए निर्यात बाध्यता हेतु इसका प्रयोग करने के ;
- (viii) कि जहां उक्त प्राधिकार के प्रति शर्त (iii) के तहत बंधपत्र दायर किया गया है और उप सीमाशुल्क आयुक्त अथवा सहायक सीमाशुल्क आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा इसका विमोचन नहीं किया हो, वहां उपर्युक्त सामग्री को किसी अन्य विनिर्माता को प्रासंस्करण हेतु जॉब कार्य से संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रक्रिया को अपनाते हुए वास्तविक प्रयोगकर्ता शर्त के तहत अंतरित किया जा सकता है ;
- (ix) किसी वाणिज्यिक निर्यातकर्ता को जारी किए गए उक्त प्राधिकार के संबंध में, -
- (क) उक्त प्राधिकार में समर्थक विनिर्माता का नाम और पता विनिर्दिष्ट किया जाता है और शर्त (iii) के निबंधनों के अनुसार आयातकर्ता द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित बंधपत्र, मर्चेन्ट निर्यातकर्ता और समर्थक विनिर्माता द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने के लिए संयुक्त रूप से निष्पादित किया जाएगा ; और
- (ख) निर्यात बाध्यता का उन्मोचन करने के लिए ऐसे समर्थक विनिर्माता के कारखाने में छूट प्राप्त सामग्रियों का उपयोग किया जाता है और उक्त मर्चेन्ट निर्यातक द्वारा इसे अंतरित या बेचा या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि शर्त (v) में निर्दिष्ट निर्यात बाध्यता का पूरी तरह से निर्वहन न कर दिया गया हो ।

2. पैराग्राफ 1 की शर्त (v) में यथानिर्दिष्ट निर्यात बाध्यता का निर्वहन करने के बाद, क्षेत्रीय प्राधिकारी उक्त प्राधिकार और/अथवा इसके तहत आयातित माल यथानिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के तहत जो अंतरण की अनुमति प्रदान करेंगे ।

3. जहां सामग्रियां दोषपूर्ण या उपयोग के लिए अनुपयुक्त पायी जाती हैं वहां उक्त सामग्रियों का उनके आयात करने पर शुल्क के संदाय की तारीख से तीन वर्ष के भीतर विदेशी प्रदायकर्ता को वापस पुनःनिर्यात किया जा सकेगा ।

बशर्ते सामग्रियों के पुनः निर्यात के समय उप सीमाशुल्क आयुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त, जैसा भी मामला हो के समाधानप्रद रूप में यह पहचान की जाती है कि यह वही सामग्री है जो आयात की गई थी ।

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ -

- (i) “विदेश व्यापार नीति” का अर्थ भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की दिनांक 7 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या 1/2006 के अधीन प्रकाशित विदेश व्यापार नीति 2004-2009 से अभिप्रेत है ;
- (ii) “क्षेत्रीय प्राधिकारी” से विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अधीन नियुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार या उक्त अधिनियम के अधीन प्राधिकार मंजूर करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है ।
- (iii) “सामग्रियों” से निम्नलिखित अभिप्रेत है -
 - (क) परिणामी उत्पाद के विनिर्माण के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्रियों, संघटक, मध्यवर्ती, खपने योग्य सामग्री, उत्प्रेरक और पुर्जे ;
 - (ख) अनुज्ञप्ति के मूल्य सीमा के दस प्रतिशत के भीतर ऐसे अनिवार्य अतिरिक्त पुर्जे जिन्हें परिणामी उत्पाद के साथ निर्यात किया जाना अपेक्षित है ;
 - (ग) परिणामी उत्पाद के विनिर्माण के लिए अपेक्षित ईंधन ; और
 - (घ) परिणामी उत्पाद को पैक करने के लिए अपेक्षित पैकेजिंग सामग्री ।
- (iv) “विनिर्माण” शब्द का अर्थ वही है जो विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 9.37 में इसे दिया गया है ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2006

No. 40/2006-CUSTOMS

G.S.R. 260(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts materials imported into India against a Duty Free Import Authorisation issued in terms of paragraph 4.4.1 and 4.4.2 of the Foreign Trade Policy (hereinafter referred to as the said authorisation) from the whole of the duty of Customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and from the whole of the additional duty, safeguard duty and anti-dumping duty leviable thereon, respectively, under Sections 3, 8 and 9A of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions namely :—

- (i) that the description, value and quantity of materials imported are covered by the said authorisation and the said authorisation is produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit:

Provided that in respect of resultant product specified in paragraph 4.55.3 of the Hand Book of Procedures (Vol.I) of the Foreign Trade Policy, the materials permitted in the said authorisation or a duty free import authorisation for intermediate supply, as the case may be, shall be of the same quality, technical characteristics and specifications as the materials used in the said resultant product.

Provided further that in respect of the said resultant product the exporter shall give declaration with regard to the quality, technical characteristic and specifications of materials used in the shipping bill;

- (ii) that where import takes place after fulfilment of export obligation, the shipping bill number(s) and date(s) and quantity and Free on Board (FOB) value of the resultant product are endorsed on the said authorisation:

Provided that where import takes place before fulfilment of export obligation, the quantity and FOB value of the resultant product to be exported are endorsed on the said authorisation;

- (iii) that the importer at the time of clearance of the imported materials executes a bond with such surety or security and in such form and for such sum as may be specified by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself to pay on demand an amount equal to the duty leviable, but for the exemption contained herein, on the imported materials in respect of which the conditions specified in this notification have not been complied with, together with interest at the rate of fifteen percent per annum from the date of clearance of the said materials :

Provided that bond shall not be necessary in respect of imports made after the discharge of export obligation in full;

1308 GI/06-2

- (iv) that the imports and exports are undertaken through seaports at Mumbai, Kolkata, Cochin, Magdalla, Kakinada, Kandla, Mangalore, Marmagoa, Chennai, Nhava Sheva, Paradeep, Pipavav, Sikka, Tuticorin, Visakhapatnam, Dahej, Mundhra, Nagapattinam, Okha, Bedi (including Rozi-Jamnagar), Muldwarka, Porbander, Dharamatar and Vadinar or through any of the airports at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Mumbai, Kolkata, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Chennai, Srinagar, Trivandrum, Varanasi, Nagpur, Cochin, Rajasansi (Amritsar) and Lucknow (Amausi) or through any of the Inland Container Depots at Agra, Bangalore, Coimbatore, Delhi, Faridabad, Gauhati, Guntur, Hyderabad, Jaipur, Jalandhar, Kanpur, Ludhiana, Moradabad, Nagpur, Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Surat, Tirupur, Varanasi, Nasik, Rudrapur (Nainital), Dighi (Pune), Vadodara, Daulatabad (Wanjarwadi and Maliwada), Waluj (Aurangabad), Anaparthi (Andhra Pradesh), Salem, Malanpur, Singanalur, Jodhpur, Kota, Udaipur, Ahmedabad, Bhiwadi, Madurai, Bhilwara, Pondicherry, Garhi Harsaru, Bhatinda, Dappar (Dera Bassi), Chheharata (Amritsar), Karur, Miraj, Rewari, Bhusawal, Jamshedpur, Surajpur, Dadri, Tuticorin, Kundli, Bhadohi, Raipur, Mandideep, Durgapur and Babarpur or through the Land Customs Station at Ranaghat, Singhabad, Raxaul, Jogbani, Nautanva (Sonauli), Petrapole, Mahadipur, Nepalganj Road, Dawki, Agartala, Sutarkhandi, Amritsar Rail Cargo and Attari Road or Special Economic Zone as specified in the notification issued under section 76A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

Provided that the Commissioner of Customs may, by special order or by a Public Notice and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export from any other seaport/airport/inland container depot or through any land customs station;

- (v) that the export obligation as specified in the said authorisation (both in value and quantity terms) is discharged within the period specified in the said authorisation or within such extended period as may be granted by the Regional Authority by exporting resultant products, manufactured in India which are specified in the said authorisation and in respect of which facility under rule 18 (rebate of duty paid on materials used in the manufacture of resultant product) or sub-rule 2 of rule 19 of the Central Excise Rules, 2002 or CENVAT credit under CENVAT credit rules, 2004 in respect of materials imported/procured against the said authorisation has not been availed :

Provided that an Advance Intermediate authorisation holder shall discharge export obligation by supplying the resultant products to the exporter in terms of paragraph 4.1.3 (ii) of the Policy;

- (vi) that the importer produces evidence of discharge of export obligation to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, within a period of thirty days of the expiry of period allowed for fulfilment of export obligation, or within such extended period as the said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, may allow;
- (vii) that exempt materials shall not be disposed of or utilised in any manner, except for utilisation in discharge of export obligation, before the export obligation under the said authorisation has been discharged in full;
- (viii) that where the Bond filed under condition (iii) against the said authorisation has not been redeemed by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, the unutilised material may be transferred to any other manufacturer for processing under actual user condition after complying the central excise procedure relating to job work;
- (ix) that in relation to the said authorisation issued to a merchant exporter,-

- (a) the name and address of the supporting manufacturer is specified in the said authorisation and the bond required to be executed by the importer in terms of condition (iii) shall be executed jointly by the merchant exporter and the supporting manufacturer binding themselves jointly and severally to comply with the conditions specified in this notification; and
- (b) exempt materials are utilised in the factory of such supporting manufacturer for discharge of export obligation and the same shall not be transferred or sold or used for any other purpose by the said merchant exporter until the export obligation specified in condition (v) has been discharged in full.

2. After discharge of export obligation as specified in condition (v) of paragraph 1, the Regional Authority shall permit transfer of the said authorisation and/or the goods imported under it subject to such conditions as may be specified.

3. Where the materials are found defective or unfit for use, the said materials may be re-exported back to the foreign supplier within three years from the date of payment of duty on the importation thereof:

Provided that at the time of re-export the materials are identified to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, as the materials which were imported.

Explanation – For the purposes of this notification,-

- (i) “Foreign Trade Policy” means the Foreign Trade Policy 2004-2009 published vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, No.1/2006 dated the 7th April, 2006;
- (ii) “Regional Authority” means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorized by him to grant an authorisation under the said Act;
- (iii) “Materials” means -
 - (a) raw materials, components, intermediates, consumables, catalysts, and parts which are required for manufacture of resultant product;
 - (b) mandatory spares within a value limit of ten per cent of the value of the authorisation which are required to be exported alongwith the resultant product;
 - (c) fuel required for manufacture of resultant product; and
 - (d) packaging materials required for packing of resultant product.
- (iv) “manufacture” has the same meaning as is assigned to it in paragraph 9.37 of the Foreign Trade Policy.

[F. No. 605/36/2006-DBK (Pt.)]

JAGMOHAN SINGH, Under Secy.